भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1447

जिसका उत्तर मंगलवार, 02 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

विद्युत चालित वाहनों को अपनाना

1447. डॉ. कंभमपति हरिबाबू:

श्री प्रेम दास राई:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं लागू की हैं/नीतिगत पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में आबंटित/व्यय की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग): राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के अंतर्गत भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को और तेजी से अपनाने और उनके विनिर्माण करने की एक स्कीम का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश में भरोसेमंद, किफायती और दक्ष इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के प्रगामी प्रवर्तन को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है जो स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं के संवर्धन और विकास के लिए सरकार-उद्योग के बीच सहयोग, आवश्यक आधारभूत ढांचे, उपभोक्ता जागरूकता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपभोक्ता की निष्पादन और कीमत संबंधी अपेक्षाओं को पूरा कर सके; जिसके परिणामस्वरूप भारत 2020 तक विश्व में एक्सईवी दुपहिया तथा चौपहिया वाहन बाजार में अग्रणी देश के रूप में उभर सकेगा। इस मिशन का लक्ष्य लोगों को एक ऐसी स्वच्छ परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है जो जीवाश्म ईंधन पर आधारित गैसोलीन पर निर्भर न हो।

****